नईदुनिया

ब्रिटेन ने अवैध आव्रजन पर नकेल कसने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की

लंदन

ब्रिटेन की सरकार ने अवैध आव्रजन पर नकेल कसने के उपायों के तहत मानव तस्करी करने वाले गिरोहों से निपटने और ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाले अवैध वित्तपोषण को रोकने के लिए गुरुवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।

सरकार ने कहा है कि नए प्रतिबंध अनियमित प्रवासन और संगठित आव्रजन अपराध को लक्षित करने के लिए हैं, जिससे अधिकारियों को खतरनाक यात्राएं करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित करने की अनुमति मिल जाएगी। नई प्रतिबंध व्यवस्था इस वर्ष के भीतर लागू होने की उम्मीद है।

सरकार के विशेषज्ञ कानून प्रवर्तन और परिचालन गृह कार्यालय के सहकर्मियों के साथ मिलकर वित्तीय प्रवाह को उनके स्रोत पर ही रोकने और यूरोप में खतरनाक समुद्री पारगमन सहित अनियमित प्रवासी आंदोलनों को सुविधाजनक बनाने वाले तस्करों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं।

नये प्रतिबंध को लेकर प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने कहा, हमें अपनी सीमाओं के उल्लंघन में मदद करने वाले अपराध गिरोहों को खत्म करना होगा। यूरोप भर में तस्करों को कमजोर लोगों की तस्करी करने की अनुमति देने वाले अवैध वित्तीय गिरोहों को कमजोर करके, हम परिवर्तन की अपनी योजना को पूरा करेंगे और यूके की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, प्रधान मंत्री कीर स्टारमर ने कहा। इसका मतलब है कि हम अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया में साहसिक और अभिनव बनें ताकि हम कोई कसर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने वाले वर्षों में लोगों की जान बचाने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

न्यूज ब्रीफ

ट्रंप का हर एक दांव हुआ फेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा तो होकर रहेगी

वाशिंगटन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले एक ऐसी मुसीवत उनके सामने आ गई जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए उन्होंने कई तरह के दांव चले हैं लेकिन उन्हे कामयाबी नहीं मिल पाई है। अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रंप को सजा तो होकर रहेगी। कभी हाईकोर्ट जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर रहम दिखाने से इनकार कर दिया है। जी हां, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क में चल रहे हश मनी मामले में अपनी सजा टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5-4 के फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि अब जज जुआन एम मर्चेन यानी शुक्रवार को ट्रंप 10 जनवरी को सजा सुना सकेंगे। ट्रंप को हश मनी केस मामले में दोषी ठहराया गया था। आरोप है कि ट्रंप ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.3 लाख डॉलर हश मनी (चुप रहने के बदले पैसे) के तौर पर देने की कोशिश की थी। ट्रंप ने डेनियल्स के साथ किसी भी तरह के संबंध होने या कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। हालांकि, जज मर्चेन पहले ही कह चुके हैं कि वो ट्रंप को जेल नहीं भेजेंगे और न ही उन पर कोई जुर्माना लगाएंगे या प्रोबेशन पर रखेंगे।

इटली की पीएम बोलीं- ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ऐसा कुछ नहीं करेंगे

रोम। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती के चर्चे अक्सर होते रहते हैं। ड्रेसिंग सेंस के साथ ही उनके हावभाव तक को लोग नोटिस करते हैं। उनकी हर एक अदा पर सबकी निगाहें रहती हैं। ईयर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके एपियरेंस ने आकर्षित किया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने डोमेस्टिक के साथ ही इंटरनेशनल मसलों पर भी अपनी राय व्यक्त की है। रूस-यूक्रेन से लेकर ग्रीनलैंड तक से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मेलोनी अपने बयान के लिए भी चर्चा में रहती हैं। ग्रीनलैंड का विवाद अभी गहराया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के कब्जे में करने की बात कही है। साथ ही पनामा नहर को लेकर भी ट्रंप ने बड़ी बात कही है। पीएम मेलोनी ने उम्मीद जताई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी रष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और पनामा नहर के मुद्दे पर चीन को टारगेट करते हुए बयान दिया है। पीएम मेलोनी ने कहा कि ट्रंप का लक्ष्य चीन था। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की ओर से दिए गए बयान पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के रष्ट्रपति बनने के बाद वह यूक्रेन को यूं ही नहीं छोड़ देंगे। यूक्रेन के साथ अमेरिका पहले की ही तरह खड़ा रहेगा। पीएम जॉर्जिया मेलोनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है।

जमानत पर 84 दिन बाद रिहा हुए रवि लामिछाने, काठमांडू जिला अदालत में होंगे हाजिर

काठमांडू। सहकारी बैंक से करोड़ों की ठगी मामले में पिछले 84 दिनों से पोखरा पुलिस की हिरासत में चल रहे पूर्व उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने गुरुवार की शाम को जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन ही उन्हें काठमांडू की जिला अदालत में पेश होना होगा। पोखरा के सूर्यदर्शन सहकारी बैंक में ठगी मामले में पूछताछ और बयान के बाद जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत पोखरा ने 9 जनवरी को रवि लामिछाने को 65 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया। चूंकि, रवि लामिछाने को पोखरा के अलावा चार अन्य जिलों के सहकारी बैंक घोटाले में प्रमुख अभियुक्त बनाया गया है, इसलिए उन्हें शुक्रवार को सबसे पहले काठमांडू जिला अदालत में पेश होना होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा ने बताया कि काठमांडू जिला अदालत में पेश होने के लिए रवि ही विमान से काठमांडू पहुंच रहे हैं। काठमांडू के स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बैंक घोटाले में रवि लामिछाने को प्रमुख आरोपित बनाया गया है, इसलिए यहां से भी उन्हें जमानत लेनी होगी। इस पूरे मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के प्रमुख दीपक थापा ने बताया कि उनकी तरफ से पोखरा की जिला अदालत में रवि को काठमांडू पुलिस के हवाले करने की अर्जी दी गई थी, लेकिन रवि के वकील की तरफ से उनके खुद ही हाजिर होने की शर्त पर काठमांडू पुलिस के हवाले नहीं किया गया था।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून के वकीलों ने दूसरे हिरासत वारंट के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर की

सियोल

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल के वकीलों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने के लिए उन्हें हिरासत में लेने के लिए दूसरे वारंट के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर की है। यून गैप-ग्यून और महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति की कानूनी बचाव टीम के अन्य सदस्यों ने विदेशी समाचार आउटलेट्स के साथ एक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

जिसमें कहा गया कि संवैधानिक न्यायालय के साथ क्षमता विवाद पर निर्णय के लिए अनुरोध दायर किया गया था। पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति यून के विचारों को साझा करते हुए यून गैप-ग्यून ने कहा कि पहले और दूसरे वारंट जारी करने वाले न्यायाधीश और हमारे आपत्ति (पहले वारंट पर) को खारिज करने वाले न्यायाधीश ने न केवल गलत कानूनी व्याख्या की, बल्कि गलत कानूनी आवेदन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून के बारे में अनुमान और अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्याएं हैं, जो इसे अवैध होने की अत्यधिक संभावना बनाती हैं। हमारी (वकीलों की) टीम ने पहले वारंट के विरुद्ध भी यही कदम उठाए लेकिन संवैधानिक न्यायालय ने वारंट समाप्त होने से पहले किसी भी अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल, 14 दिसंबर को नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग लगाए जाने के बाद से राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से नज़रों से दूर हैं। पत्रकारों को एक सवाल के जवाब में वकील यून गैप ने कहा कि राष्ट्रपति विश्वास करते हैं कि मार्शल लॉ लागू करना हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मूड बनाने में भूमिका निभा रहा है। बता दें कि संसद द्वारा पिछले साल 14 दिसंबर को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने के बाद यून की राष्ट्रपति पद की शक्तियों को निलंबित कर दिया गया था। इसी के बाद सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय ने मंगलवार को वारंट जारी किया जब जांचकर्ताओं ने अपने प्रारंभिक वारंट के विस्तार के लिए आवेदन किया, जो पिछले दिन समाप्त हो गया था। पिछले शुक्रवार को वारंट को निष्पादित करने का प्रयास विफल हो गया था, जब जब यून के अंगरक्षकों ने जांचकर्ताओं को आधिकारिक राष्ट्रपति निवास में प्रवेश करने से रोक दिया था।

लॉस एंजिल्स में जंगल की आग : बाइडेन की टीम तय करेगी अगला कदम

कैलिफोर्निया। लॉस एंजिल्स के जंगलों में लगी भीषण आग में काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सुबह, मुझे लॉस एंजिल्स के जंगल में लगी आग के नवीनतम प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति जेम्स कार्टर की सेवा के बाद, वह अपनी टीम के साथ एक और ब्रिफिंग आयोजित करेंगे और देशवासियों के लिए इस आपदा पर प्रतिक्रिया पर अपने विचार साझा करेंगे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन (कैल फायर) ने जानकारी देते हुए कहा कि अग्नि की प्रकृति जिसमें छोटी और लंबी दूरी से आग का पता लगाना भी शामिल है, एक चुनौती बना हुआ है। लॉस एंजिल्स शहर के पश्चिम में 32 किमी दूर स्थित एक समृद्ध समुदाय में, कई ऐतिहासिक स्थल, जिनमें ग्रीक और रोमन प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाला शानदार गेट्टी विला संग्रहालय और मध्य शताब्दी का आधुनिक ईम्स हाउस भी आग के खतरे में है। वह, इस भयानक आग से पैलिसेड्स के तीन स्कूलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन और पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार शाम को लगी ईटन की आग ने लॉस एंजिल्स के दो पड़ोसी शहरों अल्ताडेना और पासाडेना के पास 10,600 एकड़ (42.9 वर्ग किमी) से अधिक क्षेत्र को जला दिया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि जंगलों में लगी आग अब विकराल रूप ले चुकी है। यह आग फैलकर अब लॉस एंजेलिस और हॉलीवुड हिल्स में तबाही मचा रही है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत कर खबर है।

जल्द खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध, ट्रंप से मिलना चाहते हैं पुतिन

रूसी राष्ट्रपति ने कहा था-दूसरे पक्ष को भी समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए

वाशिंगटन

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए बैठक का शेड्यूल तैयार करवाया जा रहा है। ट्रंप ने मार-ए-लागो में रिपब्लिकन गवर्नर्स के साथ बैठक से पहले कहा कि पुतिन मुझसे मिलने को बेताब हैं। पुतिन सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। हमें इस युद्ध को खत्म करना होगा, इसने बहुत तबाही मचा दी है। ऐसे में हम इस मुलाकात का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बैठक के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई।

ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में उनकी वापसी से 22 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन पर रूस के हमले के राजनयिक समाधान की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 175 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद देने का वादा किया था, जिसमें 60 अरब डॉलर से ज्यादा की सुरक्षा सहायता भी है। हालांकि, ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इसे लेकर असमंजस है कि क्या यूक्रेन को अमेरिका की ओर से मिलने वाली मदद जारी रहेगी या नहीं।

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा था कि पुतिन, ट्रंप के मिलने की उनकी इच्छा का स्वागत करते हैं लेकिन अभी तक ट्रंप की ओर से इस तरह का कोई औपचारिक अनुरोध नहीं आया है। इससे पहले पिछले महीने पुतिन ने कहा था कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में यूक्रेन को लेकर समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है।

पुतिन ने कहा था कि लगता है जो यूक्रेनी नागरिक लड़ना चाहते हैं वे भाग जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो लड़ना चाहता हो। हम तैयार हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को भी बातचीत और समझौते दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने की कसम खाई है, लेकिन इस जंग को किस तरह खत्म करना है, इसे लेकर अभी तक उन्होंने कोई खाका पेश नहीं किया है।

यिओल के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके समर्थक

सियोल में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक यिओल के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके समर्थक।

नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय दो दिवसीय बैठक काठमांडू में शुरू हुई

काठमांडू

नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक शुक्रवार से काठमांडू में शुरू हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन संधि की समीक्षा करके आवश्यक फेरबदल करने पर चर्चा की जानी है। से शुरू हुई अंतर सरकारी समूह की बैठक में व्यापार तथा परिवहन संधि की समीक्षा करना प्रमुख एजेंडा है।

इस बैठक का नेतृत्व भारत के वाणिज्य सचिव सुशील बरथवाल, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की कर रहे हैं। दोनों तरफ से वाणिज्य के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। व्यापार तथा परिवहन संधि के किन प्रावधानों को बदलना है, उसको लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा की जा रही है।

नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता बाबूराम अधिकारी ने बताया कि नेपाल ने भारत की ओर से नेपाली उत्पादों के निर्यात पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए मांग की है, जिस पर भारत की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। नेपाल और भारत के बीच अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक नए समझौते पर बैठक के आखिरी दिन शनिवार को हस्ताक्षर करने की भी तैयारी है। इस समझौते के तहत चीन से नेपाल के रास्ते भारत में होने वाले तस्करी को रोकने के लिए कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

एलन मस्क ने वोक वायरस पर हमला कर जर्मनी की राजनीति में मचाई हलचल

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के फैसलों को अजीब और गलत बताया

वाशिंगटन

टेस्ला का मालिक एलन मस्क ने जर्मनी की राजनीति में अपने तीखे बयान से हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया एक्स पर एक लाइव स्पेस में एलन मस्क ने जर्मनी की दक्षिणपंथी नेता ऐलिस वीडेल का समर्थन करते हुए कहा कि वोक वायरस ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया है।

मस्क ने ऐलिस वीडेल को जर्मनी को चलाने में सबसे योग्य उम्मीदवार बताया और जर्मन नागरिकों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। मस्क और वीडेल ने जर्मनी की ऊर्जा नीति, शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक रुझानों पर खुलकर बातचीत की। मस्क ने जर्मनी द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने के फैसलों को सबसे अजीब और गलत कदम बताया है।

वीडेल ने जर्मनी की शिक्षा प्रणाली को वामपंथी और वोक एजेंडा से प्रभावित बताया। उन्होंने कहा कि की पीढ़ी जेंडर स्टडीज जैसे विषयों पर ध्यान देती है, लेकिन असली शिक्षा से वंचित हो रही है। मस्क ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि वोक माइंड वायरस ने जर्मनी में संस्कृति और नीति को गहरा नुकसान पहुंचाया है। मस्क ने वीडेल की पार्टी एएफडी के लिए भी खुलकर समर्थन किया है। यह पार्टी अपने दक्षिणपंथी रुझानों और प्रवास विरोधी विचारों के लिए जानी जाती है। जर्मनी के आगामी चुनावों से पहले, एएफडी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है।

एलन मस्क की टिप्पणियों ने पूरे यूरोप में विवाद खड़ा कर दिया है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज़ ने मस्क पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है, जबकि फ्रांस ने यूरोपीय संघ को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। वोक शब्द जो सतर्कता और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा है, पश्चिमी समाज में एक सांस्कृतिक विवाद का केंद्र बन गया है। समर्थकों का कहना है कि यह नस्लवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक प्रगतिशील विचार ।

खौफ में जी रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जहां जाते हैं पहले लॉकडाउन लगता है

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में फिदायनी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना का काफिला जब तुरबत शहर से 8-10 किलोमीटर दूर बेहमान इलाके से गुजर रहा था तभी बीएलए का फ़िदायीन हमला हो गया। जिसमें पाकिस्तानी फ्रंटियर फोर्स के 47 सैनिक मारे गए। 30 से ज्यादा के घायल होने हो जाते हैं। बलूचिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर तुर्बत का दौरा करने पहुंचे। यह दौरा बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) द्वारा एक आत्मघाती हमले के बाद हुआ था। उनके तुर्बत आने से पहले सुरक्षा के इंतेजाम किए गए। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्बत आने से पहले शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। कई इलाकों को पूरी तरह से लॉकडाउन में डाल दिया गया था। पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी सेना ने तुर्बत के तालीमी चौक से डी-बालोच तक के रास्तों को सील कर दिया था। इसके अलावा ओवरसीज और सैटेलाइट टाउन जैसे इलाकों को पूरी तरह से घेर लिया गया था। घटना स्थल के नजदीकी इलाकों जिसमें शाही तुम्प, बहमन, डंक और गोददान में भी अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई थी। चीफ के दौरे से पहली सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम तो किए जाते हैं लेकिन ऐसा इंतज़ाम कि पूरे इलाक़े को लॉकडाउन कर दिया। आम यात्रियों की लंबी कतारें सड़कों पर लग गई थीं।